आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 26.06.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा––प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण और हित में नया अधिनियम लाया जाएगा।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार कराने को मंजूरी दी।
- प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल वाले क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांवों को गोद लिया।

भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में कल शाम भारतीय संरक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में जहां भारत में 47 टाइगर रिजर्व थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है।

01 बाइट– भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, 28 सेकेण्ड

सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक संरक्षण ज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण करने और उसे उपयोग में लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

02 बाइट– भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, 39 सेकेण्ड

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे परंपरागत तरीकों से आगे बढ़ते हुए विज्ञान, तकनीक और सहानुभूति को संरक्षण के केंद्र में रखें।

गौरतलब है कि यह तीन दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन 27 जून तक चलेगा, जिसमें देश–विदेश से सैकड़ों छात्र, शोधकर्ता, वन अधिकारी और संरक्षण विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

नया अधिनियम

राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण और हित में नया अधिनियम लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ''संविधान हत्या दिवस'' कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाएंगे, जिसके निर्देश श्री धामी ने कार्यक्रम के दौरान दिये। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे बढ़ाने के निर्देश भी दिये।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

देहरादून में बरसात के मौसम में भी हर घर तक स्वच्छ और निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। मुख्यमंत्री के सुशासन संकल्प के तहत जिला प्रशासन पेयजल से जुड़ी समस्याओं का हर दिन समाधान करने में जुटा है। 14 अप्रैल से 17 जून के बीच कंट्रोल रूम को पेयजल से जुड़ी 167 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 162 का समाधान किया जा चुका है।

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो शिकायतों की नियमित निगरानी कर रही है। साथ ही पेयजल आपूर्ति से जुड़े सात विभागों के अधिकारी 20 अप्रैल से चौबीसों घंटे जिला कंट्रोल रूम में तैनात हैं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के दौरान जलापूर्ति बाधित न हो और सभी जल स्रोतों व टैंकों का नियमित क्लोरीनेशन कर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेयजल से जुड़ी हर शिकायत का समाधान उसी दिन किया जाना चाहिए और हर घर तक रोज़ाना स्वच्छ पानी की निर्बाध आपूर्ति प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य है।

पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या के लिये कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 0135–2726066 और 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।

दो बार बोर्ड परीक्षा

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड–सी.बी.एस.ई ने आज घोषणा की अगले साल से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित होंगी। एक रिपोर्ट–

ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल वाले गांवों को गोद लिया है। इसका उद्देश्य दूरस्थ गांवों का समग्र विकास करना है। अधिकारियों ने इन गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं करीब से समझनी शुरू कर दी हैं और अब इन क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

अधिकारी अपने पहले कार्यक्षेत्र में हुए बदलावों का मूल्यांकन कर रहे हैं और वे इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि सीएसआर और अन्य संसाधनों के ज़रिये गांव के सामाजिक और आर्थिक स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही, विकास योजनाओं की धनराशि के शत–प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

कार्यशाला आयोजित

राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल नीतियों, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधनों की सुविधा पर चर्चा के लिये देहरादून में कल एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए नीतिगत सुधारों, अवसंरचना, और क्षेत्रीय सिनेमा की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया। यह कार्यशाला राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। कार्यशाला में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, विशेषज्ञ, और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला में बताया गया कि फिल्म निर्माताओं की सहूलियत के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित करने की दिशा में भी पहल की जा रही है, जिसमें शूटिंग लोकेशन, उपकरण, कलाकार और लॉजिस्टिक्स जैसी जानकारियां एकीकृत होंगी।

रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहले खेल को उपेक्षा की नजर से देखा जाता था, लेकिन अब युवा बड़ी संख्या में इसे करियर विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, नौकरियों में पदक विजेताओं को चार प्रतिशत आरक्षण जैसी योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये बात उन्होंने हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में विजेताओं को सम्मानित करते हुए कही। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश को सैन्य भूमि के साथ खेल भूमि बनाने की दिशा में सरकार ने जरूरी बुनियादी काम कर दिए हैं और अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों के युवा कंधों को उठानी होगी।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक जारी, आज फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई– इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है पंचायतों में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हो रही सुनवाई।

कांवड़ यात्रा के लिए केंद्र सरकार से मांगी अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनी– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण खबर में लिखता है– पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश।

आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर देशभर के साथ उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर रही है... इस खबर के शीर्षक में हिन्दुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखता है– लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण तो विधेयक लाएगी सरकार...आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में ऐलान...

स्वच्छता मिशन पंचायती राज के हवाले– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है कैबिनेट की अगली वित्तीय वर्ष से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को देने पर मुहर।

2026 से साल में दो बार होगी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा, पहली परीक्षा अनिवार्य– इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी मई में होगी आयोजित।

और उत्तराखंड के मौसम की खबर पर अमर उजाला लिखता है– प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 33 मार्ग बंद।